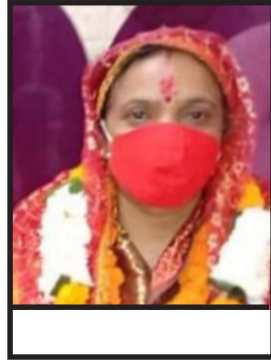




गुरुकृपा दर्पण

UTTHIN/2022/85670

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक



वर्ष : 04

अंक : 28

हरिद्वार

शनिवार, 26 जुलाई, 2025

मूल्य : एक रुपया

पृष्ठ : 4

प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जाए: मुख्यमंत्री

जतिन शर्मा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जाए। जर्जर एवं असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां भी स्कूल भवन मरम्मत योग्य हो, वहां शीघ्र मरम्मत कराया जाए और जहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो, वहां उसकी कार्य योजना बनाकर तत्परता से क्रियान्वयन किया जाए। प्रदेश के सभी पुलों का भी सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनका आवश्यकतानुसार मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया



जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलों की स्थिति पर नियमित निगरानी रखी जाए और कहीं भी जर्जर पुलों के कारण

कोई जनहानि न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रियुगीनारायण और राज्य के अन्य स्थल जो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में

विकसित किये जा रहे हैं, उनकी कार्यवाही में तेजी लाई जाय। यह राज्य के पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन स्थलों के विकास में गुणवत्ता, सुविधा और सांस्कृतिक गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, अन्य राज्यों की वेडिंग पॉलिसी का अध्ययन भी किया जाए ताकि उत्तराखंड में एक प्रभावी और आकर्षक वेडिंग डेस्टिनेशन नीति विकसित की जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राज्य में दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन विकसित किये जाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को सुदृढ़ करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी सशक्त करेगी। संबंधित विभागों को इस दिशा में आपसी समन्वय के साथ ठोस कार्य योजना बनाकर कार्य

करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, आईजी के.एस.नगन्याल, अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद थे।

17 पशुओं को गोसदन भेजा

चम्पावत। डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर 17 पशुओं को गोसदन भेजा गया। सीवीओ डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल ने बताया कि इस कदम से निराश्रित पशुओं की समुचित देखभाल हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सभी पशुओं की इयर-टैगिंग के बाद यहां पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सुमित कुमार, तारा दत्त भट्ट, शेखरानंद जोशी और जगदीश सिंह बिष्ट मौजूद रहे।

भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लम्बा कार्यकाल

जतिन शर्मा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लम्बा कार्यकाल पूर्ण करने पर प्रदशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है। उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि

भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं और कई नये ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को देश और दुनिया के सामने रखा है। प्रत्येक भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका नेतृत्व हम सभी को प्रदान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है।

सैनी आश्रम की संपत्ति को खुरदबुर्द करने का आरोप लगाया

हरिद्वार। सैनी आश्रम के संचालन को लेकर दो गुटों में विवाद जारी है। शक्रवार को देवपुरा में आश्रम से जुड़े एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर आश्रम की संपत्ति को खुरदबुर्द करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगामी 3 अगस्त को सैनी आश्रम में समाज की आमसभा करने की घोषणा की। मनोज सैनी ने कहा कि सैनी आश्रम में भारी अनिमितताएं चल रही हैं।

जतिन शर्मा

ऋषिकेश। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने टिहरी जनक्रांति के नायक श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। बैराज रोड स्थित कैम्प कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर डॉ. अग्रवाल ने कहा कि श्रीदेव सुमन एक लेखक, पत्रकार और जननायक ही नहीं बल्कि टिहरी की ऐतिहासिक क्रांति के भी महानायक थे। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की किशोरावस्था में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर साबित कर दिया था कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना किस हद तक भरी हुई थी। इसके कारण उन्हें 14 दिन जेल रखा गया था। उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन ने बहुत छोटी उम्र में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो टिहरी आते समय श्रीदेव सुमन को 23 अगस्त 1942 को देवप्रयाग में ही गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन मुनि की रेती जेल में रखने के बाद 6 सितंबर को देहरादून जेल भेज दिया। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि ढाई महीने देहरादून जेल में रखने के बाद श्रीदेव सुमन आगरा सेन्ट्रल जेल भेज



दिया गया। जहां ये 15 महीने नजरबंद रखे गये। 84 दिन की ऐतिहासिक अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस मौके पर अमर शहीद श्रीदेव सुमन के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दायित्वधारी गिरीश डोभाल, मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी, सुरेंद्र प्रताप, बृजेश शर्मा, नितिन सक्सेना, दीपक बिष्ट, राजेंद्र बिजलवाण, चंदू यादव, सौरभ गर्ग, विमल नेगी, अखिलेश मित्तल, सुयश मिश्रा, ममता नेगी, पूनम डोभाल, पंकी धस्माना, गुड्डी कालूडा, निवेदिता सरकार, पुनीता भंडारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।

नारायण शिला के पास से टाटा सूमो चोरी

हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायण शिला क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार सवारी लेकर आए चालक की टाटा सूमो अज्ञात चोर उड़ा ले गए। पीड़ित ने कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक गंधारी, थाना रुद्रप्रयाग निवासी वसुदेव सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को वह अपनी टाटा सूमो से सवारी लेकर हरिद्वार आया था।

गुरुकृपा दर्पण

(राष्ट्रीय समाचार पत्र) को आवश्यकता है उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए ब्यूरो चीफ, कैमरा मैन, संवादाताओं की। सम्पर्क करें – 9410731129, 9548880101

सम्पादकीय



अवैध प्रवासियों की समस्या



सम्पादक - देवेन्द्र जौहरी

अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने के विवाद के बाद बिहार में बहस गरम हुई। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में भी अगले वर्ष होंगे। बूथ स्तर के कर्मचारियों का आरोप है कि घर-घर जाकर की गई जांच में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश

व म्यामांर के अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में मिले। इस सारी कवायद पर संदेह व्यक्त करने वालों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। साठ फीसद से भी कम नागरिकों के पास पक्का मकान है, केवल 14व वयस्क दसवीं तक पढ़े हैं। सवाल है, बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर रोजगार के सिलसिले में अन्य राज्यों में जा चुके हैं, उनका नाम इस सूची में शामिल करने का जिम्मा कौन लेगा। हाशिए पर खड़े लोग, दलितों, वंचितों व गरीबी रेखा के नीचे गुजार करने वालों से दस्तावेजों की सूची मांगना गैरवाजिब है। उस पर भी जिनके नाम पहले ही मतदाता सूची में मौजूद हैं और वे तीन-चार बार अपना मत प्रयोग कर चुके हैं। हैरत है कि इतने व्यापक स्तर पर बनाए गए आधार कार्ड पर सरकार और उसका समूचा तंत्र विश्वास क्यों नहीं कर पाता। सबके लिए एक सामूहिक व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती। देश के हर नागरिक के लिए एकमात्र परिचय पत्र की व्यवस्था हो, जिसके माफत समूची जनसंख्या का सटीक अंदाजा भी हो और वही नागरिकता की पहचान बने।

कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर किया स्वागत, सकुशल संपन्नता पर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कावड़ यात्रा कुशल संपन्न कराने के लिए बहुत आभार - रानीपुर विधायक आदेश चौहान

पहुंचते हैं यह आत्मविश्वास उन्हें भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास से मिलता है। हमारी सरकार ने धर्मनगरी में आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जगह जगह चिकित्सा

जतिन शर्मा
हरिद्वार। रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भगवान शिव के भक्तों से देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। कई सौ किलोमीटर पैदल चलकर मां गंगा के तट पर शिव भक्त आस्था के साथ

शिविर, पानी की आपूर्ति, सुगम मार्ग की व्यवस्था के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ड्यूटी पर तैनात है। धर्मनगरी के लोगों को शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिव भक्त कांवड़ियों के लिए हर तरह से सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देशन में तैराक दल

तैनात किये गए हैं जिससे डूबने वाले कावड़ियों को बचाया जा सके। वरिष्ठ भाजपा नेता डा. विशाल गर्ग ने कहा कि चारों ओर हर-हर महादेव के जयकारो भक्ति से शराबोर नजारा हिंदू संस्कृति को जताता है। देश दुनिया में सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है। भगवान शिव के भक्तों की सेवा अवश्य ही सुखद फल प्रदान करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कावड़ यात्रा को से कुशल संपन्न करने के लिए हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पुलिसकर्मी रात दिन कावड़ियों की सेवा में जुटे हुए हैं। कावड़ियों की सेवा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। युवा भाजपा नेता और कार्यक्रम संयोजक वासु पाराशर ने कहा कांवड़ियों का यह अद्भुत उत्साह, उनकी आस्था और शिवभक्ति हम सभी को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता डा. विशाल गर्ग, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, युवा मोर्चा जिला महामंत्री अभिनव चौहान, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, विक्रमजीत सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।

साक्ष्य संश्लेषण विभाग के तत्वाधान में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित



जतिन शर्मा
ऋषिकेश। एम्स में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान साक्ष्य संश्लेषण को समझने और इसको पढ़ने के तौर-तरीकों पर विशेष चर्चा की गयी। इस दौरान कहा गया कि साक्ष्य आधारित चिकित्सा में साक्ष्य संश्लेषण की विशेष भूमिका है जिसे सभी

चिकित्सकों को अपनाने की आवश्यकता है। एम्स के साक्ष्य संश्लेषण विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रो० मीनू सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य साक्ष्य आधारित चिकित्सा (ईबीएम) और साक्ष्य संश्लेषण को पढ़ने तथा इसके सिद्धांतों

को व्यवहारिक कौशल से सशक्त बनाना है। उन्होंने संकाय सदस्यों के लिए इस कार्यशाला को बहुलाभकारी बताया। कार्यशाला का पहला दिन साक्ष्य आधारित चिकित्सा की नींव, प्रमुख शिक्षण पद्धतियों, शैक्षिक सत्रों की योजना बनाने और व्यवस्थित समीक्षाओं के मूल्यांकन पर केंद्रित रहा। पहले दिन एम्स मोहाली की डॉ० मानवी सिंह, ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके के डॉ० निशांत जयसवाल और एम्स ऋषिकेश के डॉ० विवेक सिंह मलिक ने कार्यशाला के विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। जबकि दूसरे दिन साक्ष्य आधारित चिकित्सा का अनुप्रयोग, साक्ष्य संश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई) के एकीकरण, रेंडोमाइज्ड कंट्रोलड ट्राईल्स (आरसीटी) और नैदानिक परीक्षण सटीकता (डीटीए) अध्ययनों के मूल्यांकन, और बी.एम.जे बेस्ट प्रैक्टिस जैसे उपकरणों के माध्यम



से साक्ष्य के कार्यान्वयन जैसे विषयों को कार्यशाला में शामिल किया गया। दूसरे दिन के प्रमुख वक्ताओं में एम्स ऋषिकेश के डॉ. प्रतीक कुमार पांडा, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के डॉ० अनिल चौहान और बीएमजे ग्रुप यूके के डॉ० कीरन वॉल्श आदि शामिल थे। कार्यशाला के आयोजन सचिव व संस्थान के वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्यशाला विशेष तौर से संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए आयोजित की गयी थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सत्रों में इंटरैक्टिव लघु-समूह कार्य, आलोचनात्मक मूल्यांकन अभ्यास और सूक्ष्म-शिक्षण अभ्यास आदि विषय शामिल थे। इस अवसर पर प्रो. संजीव कुमार मित्तल, प्रो. सोमप्रकाश बसु, प्रो. श्रीपर्णा बसु, प्रो. आशी चुग, प्रो.

बलराम, एसोशिएट प्रो. डॉ० पूनम सिंह, डॉ० भावना गुप्ता, डॉ० इंतजार के अलावा विभिन्न विभागों के फेकल्टी सदस्य मौजूद रहे।



देवेन्द्र जौहरी

सहसम्पादक

जतिन शर्मा

सहसम्पादक

विक्रान्त शर्मा

कानूनी सलाहकार

जसमहिन्द्र सिंह एडवोकेट

नीति आयोग के आकांक्षा हाट को लेकर बैठक संपन्न

हरिद्वार। जनपद मुख्यालय स्थित विकास भवन रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नीति आयोग के तहत आयोजित होने वाले आकांक्षा हाट के संबंध में थी, जो कि 28 जुलाई 2025 से 2 अगस्त 2025 तक चलेगा। बैठक में आकांक्षा हाट के

प्लेस आइडेंटिफिकेशन, कैनोपी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 27 जुलाई तक समस्त तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। इस बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री कैलाश नाथ तिवारी,

जिला विकास अधिकारी श्री वेदप्रकाश, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत धिल्लियाल, डीपीओ सुलेखा सहगल, डीएसटीओ सुश्री नलिनी ध्यानी, एडीएसटीओ श्री सुबास शाक्य, जिला परियोजना प्रबंधक श्री संजय सक्सेना, सहायक प्रबंधक सेल्स श्री अमित शर्मा, एसीएमओ सहित कई अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

पारिस्थितिक और मानवीय आपदा ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

विनीत नारायण

ग्रेट निकोबार द्वीप, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, अपनी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा प्वाइंट, होने के साथ-साथ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुछ समय पहले नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित 72,००० करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ने इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार, पर्यटन और सामरिक महत्त्व का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविद्, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को नीति आयोग ने 2०21 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य इस द्वीप को एक आर्थिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। परियोजना के तहत 16,61० हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया

जाएगा जिसमें से 13०.75 वर्ग किमी. प्राचीन वन क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की '%एक्ट ईस्ट' नीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों ने इसे विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। ग्रेट निकोबार द्वीप 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2०13 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह द्वीप 1,767 प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता का घर है, जिसमें 11 स्तनधारी, 32 पक्षी, 7 सरीसृप और 4 उभयचर प्रजातियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में स्थानिक हैं। परियोजना के लिए लगभग 9.6 लाख से 1० लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी जो द्वीप के प्राचीन वन वनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगी। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। गलाथिया खाड़ी, जहां ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है, लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापोड पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2०21 में गलाथिया खाड़ी वन्य जीव अभयारण्य को डिनोटिफाई कर

दिया गया जो भारत की राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण योजना (2०21) के विपरीत है। यह कछुओं और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है क्योंकि बंदरगाह निर्माण से होने वाला प्रदूषण, ड्रेजिंग, और जहाजों की आवाजाही उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करेगी। द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (छ्त्रक) के रूप में वर्गीकृत हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परियोजना से इनके पारंपरिक क्षेत्रों का 1०ल हिस्सा प्रभावित होगा जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीविका पर खतरा मंडराएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से इन जनजातियों में रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान-सुमात्रा फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो भूकंप और सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। 2००4 की सुनामी ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन में भूकंपीय जोखिमों को कम करके आंका गया है, और विशेषज्ञों का कहना है कि

परियोजना के लिए साइट-विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन नहीं किए गए। यह एक बड़े पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है। परियोजना के लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। लेकिन ये क्षेत्र निकोबार की जैव विविधता से कोई समानता नहीं रखते। यह पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में असमर्थ है। पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन दस्तावेज को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल हवाई अड्डे का सामरिक महत्त्व हो सकता है, न कि पूरी परियोजना का। पारदर्शिता की यह कमी परियोजना की वैधता पर सवाल उठाती है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने परियोजना को '%पारिस्थितिक और मानवीय आपदा' करार दिया है। पर्यावरणविद् और नागरिक समाज संगठनों ने इसे जैव-विविधता और आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2०23 में परियोजना की पर्यावरण और वन मंजूरी की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। ग्रेट

निकोबार द्वीप परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पारदर्शी और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, आदिवासी समुदायों के साथ उचित परामर्श और भूकंपीय जोखिमों का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। साथ ही, परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता की पुनः समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि भारत में हाल में शुरू हुआ विशाखापत्तनम का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पहले से ही वैश्विक व्यापार में योगदान दे रहा है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि परियोजना क्षेत्र को कड्डू 1ः क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। आदिवासी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भूकंपीय जोखिमों के लिए साइट-विशिष्ट अध्ययन किए जाएं। निकोबार के भीतर ही प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान दिया जाए। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। भ्रामक तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर करेंगे।

तालिबान शासन को मान्यता भारत के समक्ष चुनौतियां

गिरीश पांडे

हाल में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को रूस की ओर से आधिकारिक मान्यता मिल गई है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे कई देशों की राजनयिक इंगेजमेंट के बावजूद रूस दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने अफगानिस्तान को राजनयिक मान्यता प्रदान कर दी है। इसे हम रूस का वॉकिमंच पर अप्रत्याशित और निर्णायक कदम कह सकते हैं। यह कदम ऐसे समय उठा है जब अमेरिका, भारत और यूरोप जैसे प्रमुख देश अब भी तालिबान शासन को मान्यता देने से परहेज कर रहे हैं। रूस के इस कदम के पीछे कई रणनीतिक कारण निहित हैं। मसलन, रूस, पश्चिमी दबावों से मुक्त होकर स्वतंत्र शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। अफगानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्यों की सीमा पर स्थित है, जहां रूस की पारंपरिक पकड़ रही है। तालिबान से संपर्क इसी विस्तार का हिस्सा है। रूस के निर्णय का असर अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वि राजनीति पर इसका असर पड़ने की संभावना है। 1979 में सोवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में दखल के बाद से लेकर 1989 तक मिखाइल गोर्बाचोव के अपनी सेना वापस बुलाने तक अफगानिस्तान और रूस जटिल

ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों में उलझे रहे। हालांकि, 2० साल बाद अप्रैल, 2०25 में रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाया था और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा था। अफगानी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऐसी ही एक संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत (आईएसकेपी) के मद्देनजर तालिबान से सुरक्षा सहयोग की दरकार है। इस समूह ने रूस में पिछले साल आतंकी हमले को अंजाम दिया था और जिसमें 13० लोग मारे गए थे। इसलिए रूस ने इस बार यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ध्यान देने की बात है कि अगस्त, 2०21 में अमेरिका और नाटो के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब तालिबान ने कहा था कि वह अफगानिस्तान में लिबरल शासन चलाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कड़े शिया कानून लागू कर दिए। महिलाओं के प्रति कड़ी भेदभाव वाली नीतियों की वजह से पश्चिम के देशों ने तालिबान को राजनयिक तौर पर अलग-थलग रखा है। जानकार कहते हैं कि अब चीन भी रूस के नक्शेकदम पर चलेगा और अफगानिस्तान को मान्यता देने के बारे में सोचेगा। वैसे भी अभी

रूस और चीन की '%अनिलमिटेड दोस्ती' चल रही है। जहां तक भारत का संबंध है, रूस के इस निर्णय से भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां और विकल्प उभरते हैं। पहला तो यही है कि रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। रूस द्वारा तालिबान को मान्यता देना भारत के हितों के विपरीत प्रतीत हो सकता है, विशेषकर जब अफगानिस्तान से आतंकवाद की आशंका बनी हुई हो। इसके अलावा, रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान का तालिबान से व्यवहार भारत के लिए अलग-थलग पड़ने की स्थिति पैदा कर सकता है, और तालिबान की सत्ता में मजबूती, जम्मू-कश्मीर में कट्टरपंथी ताकतों को परोक्ष समर्थन दे सकती है। इसलिए अभी भारत का तालिबान के साथ सॉफ्ट एंगेजमेंट चल रहा है, और तालिबान के साथ बिना उसे औपचारिक मान्यता दिए सीमित और नियंत्रित संवाद जारी हैं। भारत, अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की भी बराबर निगरानी कर रहा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत का दृष्टिकोण हमेशा ही अफगान के लोगों के साथ दीर्घकालिक और विशेष मित्रता से प्रेरित रहा है, और साथ ही एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत का हित सीधे जुड़ा है।

पैकेज्ड स्नैक्स में होती हैं ये खतरनाक सामग्रियां

पैकेज्ड स्नैक्स का सेवन करना कई लोगों को पसंद होता है क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। हालांकि, इन स्नैक्स में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जो पैकेज्ड स्नैक्स में मौजूद होती हैं और जिनका सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए इनसे युक्त स्नैक्स का सेवन करने से बचें।

माल्टोडेक्सट्रिन

माल्टोडेक्सट्रिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो पैकेज्ड स्नैक्स में अक्सर इस्तेमाल होता है। यह सफेद पाउडर की तरह दिखता है और इससे स्नैक्स को अधिक मीठा और स्वादिष्ट बनाया जाता है। हालांकि, माल्टोडेक्सट्रिन का सेवन शरीर में तेजी से शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है। इससे मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसके सेवन से सावधानी बरतनी चाहिए।

आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर

कई पैकेज्ड स्नैक्स में मक्खन का स्वाद देने के लिए आर्टिफिशियल बटर फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ सस्ता भी

होता है, लेकिन इसके सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आर्टिफिशियल बटर में ट्रांसफैट हो सकता है, जो दिल की बीमारियों और मोटापे का कारण बन सकती है। इसलिए पैकेज्ड स्नैक्स खरीदने से पहले उनके लेबल को ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें कि जो स्नैक्स प्राकृतिक चीजों से बने हों।

मॉडिफाइड फूड स्टार्च

मॉडिफाइड फूड स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो पैकेज्ड स्नैक्स में इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए आलू, मक्का या अन्य स्टार्चयुक्त सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इस स्टार्च को रसायनिक प्रक्रिया के जरिए बदला जाता है, जिससे इसके पोषण मूल्य कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद रसायन सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसके कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए कम से कम पैकेज्ड स्नैक्स का सेवन करें।

सोडियम नाइट्राइट

सोडियम नाइट्राइट एक प्रकार का संरक्षक है, जो पैकेज्ड स्नैक्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। हालांकि, यह रसायन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व में कांवड़ मेला 2025 सफलता पूर्वक सम्पन्न

जतिन शर्मा

हरिद्वार। शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ मेले के सुकशल, सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल हरकी पौड़ी ब्रह्म कुंड पर मां गंगा तथा श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा मां गंगा एवं श्री दक्षेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। इस कांवड़ मेले में लगभग चार करोड़ 50 लाख शिवभक्त हरिद्वार पहुंच कर गंगाजल लेकर रवाना हुए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कांवड़ मेला 2025 सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मेला सफलता पूर्वक सम्पन्न होने पर सभी शिवभक्तों सहित जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए दिन रात व्यवस्थाओं में लगे अधिकारियों, कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों एवं अर्ध सैनिक बलों का आभार एवं धन्यवाद



किया। कांवड़ यात्रा के सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के उपरांत कांवड़ मेला क्षेत्र एवं कांवड़ पटरी में चलाया जाएगा विशेष स्वच्छता अभियान-जिलाधिकारी। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रविंद्र पुरी महाराज जी भेंटकर आशीर्वाद लिया। कांवड़ यात्रा सकुशल सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड

पहुंच कर मां गंगा की पूजा अर्चना की तथा दुग्ध अभिषेक किया एवं मां गंगा के आशीर्वाद लिया एवं मां गंगा का आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और श्री दक्षेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया एवं महादेव का आभार व्यक्त किया। प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा की इस वर्ष के कांवड़ मेले में लगभग 04 करोड़ 50 लाख शिवभक्त हरिद्वार पहुंच कर गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के

लिए रवाना हुए उन्होंने कहा कि मां गंगा एवं महादेव शिव की कृपा है कि करोड़ों भक्त आने के बाद भी कांवड़ मेला सकुशल एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में कार्य किया गया तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई जिसके फलस्वरूप कांवड़ मेला सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी आभार व्यक्त किया कि जिनके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के साथ महत्वपूर्ण चुनौती यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कराई गई। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिस जवानों, पीआरडी, होमगार्ड, अर्ध सैनिक बलों अधिकारियों एवं जवानों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दिन रात अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया। उन्होंने सभी प्रशासनिक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, जनप्रतिनिधियों संत समाज, जनपद

वासियों एवं पर्यावरण मित्रों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहायक से कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। इसके साथ ही उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के प्रेस प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से पुलिस द्वारा की गई यातायात व्यवस्था से लेकर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का व्यापक स्तर से प्रचारित प्रसारित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा सकुशल एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है अब वेस्ट मैनेजमेंट को संपादित करने के लिए कांवड़ मेला क्षेत्र एवं कांवड़ पटरी मार्गों पर अगले तीन दिनों तक विशेष स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एचआरडीए सचिव मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा, एसपी सदर जितेंद्र चौधरी, एसपी सिटी पंकज गैरोला, अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर, सीओ सिटी शिशुपाल नेगी, सीओ निहारिका सेमवाल, तहसीलदार सचिन कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सभी अधिकारी एवं कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य के निर्देश

जतिन शर्मा

हरिद्वार/भगवानपुर। कार्यों में पारदर्शिता तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यालयों में उपस्थिति समय से सुनिश्चित कराए जाने के लिए सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस के तहत कार्य किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज तहसील भगवानपुर एवं विकास खंड भगवानपुर का औचक निरीक्षण कर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी सबसे पहले तहसील कार्यालय भगवानपुर पहुंचे जहां पर उन्होंने अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय में अधिकारियों एवं कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराई जाए तथा बायोमैट्रिक उपस्थिति का निरंतर प्रिंट निकलने के भी निर्देश दिए तथा बार बार देरी से कार्यालय आने वाले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी पटलों का निरीक्षण कर सभी पटल सहायकों को निर्देश दिए हैं कि उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ करे तथा सभी पत्रावलियों को रख-रखाव ठीक ढंग से करे, उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि तहसील



कार्यालय में अपनी कार्यों एवं समस्याओं को लेकर आने वाले आमजन का कार्य एवं समस्याओं का तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करे जिससे कि आम जन को बार बार तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को ये भी निर्देश दिए हैं कि उनके न्यायालय में जो तीन वर्ष से अधिक समय और अन्य लंबितवादों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को भी निर्देश दिए हैं कि वर्तमान मानसून के दृष्टिगत तहसील क्षेत्रगत ग्राम पंचायतों का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए तथा जिन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है उन क्षेत्रों की जल निकासी एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक करवाई के निर्देश दिए। विकास खंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सभी पटलों का निरीक्षण कर सभी पटल सहायकों

को आपने दायित्वों का निर्वहन तत्परता से करने के निर्देश दिए, उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका समयबद्धता के साथ भुगतान करते हुए पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य संपादित कराए जाए। विकास खंड कार्यालय के लेखाकार कक्ष का निरीक्षण करते हुए लेखाकार से ई ऑफिस संचालन के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जानकारी ली गई तो उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं खंड विकास अधिकारी को संबंधित लेखाकार को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी पत्रावलियां तैयार की जा रही हैं वह ई ऑफिस के माध्यम से पत्रावलियां

तैयार करने के निर्देश दिए, विशेष परिस्थितियों में ही ऑफलाइन पत्रावलियां तैयार की जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भगवानपुर को भी निर्देश दिए हैं कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत विशेष स्वच्छता अभियान चलाते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान क्षेत्रान्तर्गत मार्गों पर पड़े कूड़े का तत्परता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर

पनीर का सैंपल फेल होने पर होटल मालिक और मैनेजर पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा

हरिद्वार। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान शिवालिक नगर के होटल से लिया गया खुले पनीर का सैंपल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया है। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल मालिक और मैनेजर के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बीते 31 दिसंबर को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने शिवालिक नगर स्थित से एसआर ग्रांट होटल से खुले पनीर का सैंपल लिया था।

पालिका एवं तहसीलदार भगवानपुर को भी निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र का सयुक्त निरीक्षण कर क्षेत्र में सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको चिन्हित करते हुए उसको तत्काल हटाने की करवाई कि जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन व्यापारियों द्वारा पॉलीथिन का उपयोग किया जा रहा है ऐसे करने वाले के विरुद्ध नियमानुसार चालान करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी देवेन्द्र सिंह नेगी, खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गेय, तहसीलदार दयाराम, ईओ नगर पालिका भगवानपुर सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक
देवेन्द्र जौहरी द्वारा
साप्ताहिक समाचार पत्र
“गुरुकृपा दर्पण” को
रुद्र प्रिंटिंग प्रेस, ई-34,
ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
(उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं
एस-3, अशोक विहार कालोनी,
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
से प्रकाशित।
सम्पादक: देवेन्द्र जौहरी
मो. - 9997331129
E-mail :
gurukripadarpan@gmail.com